ग्रामीण भारत में सामाजिक वदलाव की वर्तमान स्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन।

डॉ0 राम समुझ सिंह, एसोशिएट प्रो0 समाजशास्त्र
लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय
गोण्डा, उ0 प्र0।

सार
भारत एक विकासशील राष्ट्र है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का कार्यबल है जो 60% से अधिक आबादी को रोजगार देता है।नतीजतन, भारत के ग्रामीण क्षेत्र की जांच और विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, जो हमारे देश की समृद्धि के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। गांवों में रहने वाले 70 प्रतिशत लोगों के साथ, ग्रामीण भारत हमारे देश का असली चेहरा दर्शाता है।भारत की समृद्धि में कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है, और इसका अध्ययन करने से देश की सामान्य वृद्धि और उन्नति को लाभ होगा। ग्राम संरचना को स्थानांतरित करने का समाजशास्त्रीय शोध ग्रामीण भारत की चुनौतियों के साथ-साथ राज्य और संघीय सरकार द्वारा उन्हें संबोधित करने के उपायों पर प्रकाश डालेगा। ग्रामीण भारत की संरचना आजादी के बाद से विकसित हुई है।हमारे देश में 500,000 से अधिक समुदाय हैं , जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग जीवन जीने का तरीका है।उनके अधिकांश मुद्दों को स्थानीय रूप से निपटाया जाता है , और उनसे निपटने के लिए उनके पास एक अच्छी तरह से परिभाषित सामाजिक व्यवस्था है।जाति के आधार पर लोगों के गहरे गहरे अलगाव ने एक स्तर-आधारित समाज की स्थापना की है जो समुदायों को एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ने से रोकता है। भारत का ग्रामीण समाज अलग-अलग भौगोलिक और जातीय पृष्ठभूमि के कारण प्रति राज्य अलग है। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की आकांक्षा रखता था जिसमें जाति , पंथ, समुदाय या भूगोल की परवाह किए बिना समावेशी प्रगति की योजना बनाई गई थी।हालाँकि , योजना के क्रियान्वयन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए क्योंकि भारतीय समुदाय सदियों पुरानी प्रथाओं का पालन करना जारी रखते हैं।यह निस्संदेह भारत में विकसित हो रही ग्राम संरचनाओं के साथ-साथ उनके विकास की सीमा की एक विस्तृत परीक्षा की आवश्यकता है।

भारतीय गांवों का इतिहास

जैसा कि हम कहते हैं , ग्रामीण भारत हमारे देश का असली चेहरा है।वहां रहने वाले लोग अपने रहन-सहन से खुश थे।शहरी जीवन शैली की सनक और शहरों में अधिक कमाने की चाहत ने पूरे समय गांवों की सोच को प्रभावित किया है।आय के बेहतर और अधिक आशाजनक स्रोत की तलाश में ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में लोगों के आंदोलन ने समकालीन भारत में गांवों की संरचना को विकृत कर दिया है।कृषि, जो हमारे आर्थिक विकास का प्राथमिक स्रोत है, की इस सामूहिक प्रवास के परिणामस्वरूप अनदेखी की जा रही है।हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि ग्रामीण निवासियों के बीच सोच में इस बदलाव का कारण क्या है।शहर की जीवन शैली जीने की इच्छा स्थानांतरण का एकमात्र कारण नहीं हो सकती है।यह मुद्दा समुदायों की मौजूदा चुनौतियों में गहराई से अंतर्निहित है।ब्रिटिश प्रशासन के दौरान , राष्ट्र में प्रत्येक गांव एक तंग समाज के रूप में कार्य करता था, जिसमें उच्च जाति समाज मानदंडों को परिभाषित करते थे।वे आत्मनिर्भर थे और जीवित रहने के लिए उन्हें बाहरी मदद की ज्यादा जरूरत नहीं थी।जाति व्यवस्था समाज की नींव और शासन संरचना हुआ करती थी , जिसमें लोगों के कर्तव्यों को पहले से परिभाषित किया जाता था और उन्हें कुछ और करने की अनुमति नहीं होती थी।ब्राह्मणों से उपदेश देने की अपेक्षा की जाती थी, क्षत्रिय योद्धा होने के लिए , और व्यास और शूद्र कम स्तरों पर काम करते थे।समाज बाहर से स्थिर लग रहा था, लेकिन दुश्मनी हमेशा एक्सपोजर के साथ बढ़ी थी।तब से , गांव की संरचना विकसित हुई है।कृषि भारतीय समुदायों को बनाए रखती है और उनके जीवन

के तरीके का आधार है।ग्रामीण इलाकों की सामाजिक संरचनाओं और दर्शन में रहने वाले लोगों को उनके निर्वाह के स्रोत से ढाला गया है।कृषि सुधार ग्राम संगठन में किसी भी बदलाव का प्राथमिक चालक होगा।इसके अलावा, सामाजिक स्तरीकरण का ग्रामीण भारत के परिवर्तन पर समान प्रभाव पड़ेगा।भारतीय गाँवों की सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं का गहन परीक्षण इस बात की अच्छी समझ प्रदान करेगा कि भारतीय गाँवों की बदलती संरचना ने पूरे देश को कैसे प्रभावित किया है।कृषि समाज वे हैं जिनका कृषि के साथ घनिष्ठ संबंध है।

भूमि केवल एक संपत्ति या कृषि के लिए एक संसाधन से अधिक है ; यह अस्तित्व की नींव है।कृषि न केवल आय का एक स्रोत है , बल्कि यह एक समुदाय की नींव भी है।यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत में त्योहारों के उत्सवों को मनाने के लिए कटाई के मौसम का उपयोग किया जाता है।कुछ का उल्लेख करने के लिए , पंजाब में बैसाखी, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल और कर्नाटक में उगादी।

ग्रामीण भारत - एक व्यापक अध्ययन

जब खानाबदोश मनुष्य झुंड में रहने लगे और एक साथ शिकार करने लगे , तो गाँव की धारणा पैदा हुई।

ये उनके झुंड के लिए स्थापित नियम , और वे सभी के द्वारा देखे गए थे।अकेले संघर्ष करने की तुलना में एक समूह के रूप में जीवित रहना कहीं अधिक आसान था।इसने एक ही भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्तियों को एक साथ आकर्षित किया, और वे बंद समुदायों में रहने लगे। ऐसे झुंडों की संरचना धीरे-धीरे विकसित हुई और अधिक संगठित हुई।सरकार के कानून बदलते रहे , जिसके परिणामस्वरूप देश भर में अलग-अलग गांवों का निर्माण हुआ।बाहरी हस्तक्षेप कम से कम किया गया था, और वे अपने सभी मानदंडों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे।

कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को स्थापित किया गया था , और इसलिए संतुलन बनाए रखा गया था।कृषि उनके अस्तित्व की नींव थी और उन्होंने अपने ग्रामीण समुदायों को स्थिरता प्रदान की।विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ , ग्रामीण सभ्यताएँ उभरने लगीं , जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद मिली। ग्रामीण समुदायों की परस्पर क्रिया ने भी भारतीय गांवों के मौजूदा स्वरूप में योगदान दिया है।समुदायों को अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया गया था , जो इस बात पर निर्भर करता था कि वे एक निश्चित स्थान पर कितने समय से मौजूद थे।उनमें से कुछ खानाबदोश समुदायों के थे जहां झुंड आगे बढ़ने से पहले कुछ महीनों तक रहता था।कुछ समुदाय कई वर्षों तक एक ही स्थान पर रहते थे जब तक कि मिट्टी की उर्वरता समाप्त नहीं हो जाती थी, जिस बिंदु पर वे अधिक उपजाऊ साइट पर स्थानांतरित हो जाते थे।एक अन्य प्रकार के स्थायी समुदाय थे जो कई वर्षों तक एक ही भूमि पर रहते थे।ऐसे कई तत्व हैं जो भारतीय गांवों के गठन को प्रभावित करते हैं , जिनमें से सभी पर हमारे समाजशास्त्रीय शोध के दायरे में चर्चा की गई है।गाँव की संरचना का निर्माण पारिस्थितिक परिस्थितियों जैसे मिट्टी , पानी और अन्य संसाधनों से बहुत अधिक प्रभावित होता है।एक स्थिर समुदाय के लिए वर्षों तक रहने के लिए संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र और खराब अस्तित्व की परिस्थितियों वाले स्थान एक खानाबदोश मानसिकता और एक गतिशील संरचना उत्पन्न करते हैं जो हमेशा बदलती रहती है।पहले , गांवों में सत्ता संरचना ज्यादातर संपत्ति के स्वामित्व , जाति और स्थिति पर आधारित थी।जमींदारों का ग्रामीण संस्कृतियों में अधिक प्रभाव था क्योंकि वे भूमि को नियंत्रित करते थे।इसी तरह , उच्च जाति के सदस्यों को उच्च सम्मान दिया जाता था और ग्रामीण समुदायों में उनका अधिक प्रभाव माना जाता था।इसके अलावा , जिनके पास स्थानीय पंचायतों में सीटें थीं , उनका ग्रामीण क्षेत्र में अधिकार था।हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद , जमींदारी और जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, और नए भूमि सुधार लागू किए गए।राजनीति ने एक पूरी तरह से नई शक्ति संरचना के गठन को प्रेरित किया।

लाभ – भारतीय बस्तियों के निर्माण में संशोधन

भूमि सुधारों के परिणामस्वरूप भारतीय समुदायों के संगठन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है।जमीनें अब जमींदारों और जागीरदारों की संपत्ति नहीं रही।किसानों को अब उनकी फसलों से लाभ हो सकता है।नवीनतम कृषि नवाचारों पर किसानों को शिक्षित करने के लिए नीतियां बनाई गई हैं।आयोग, सभी स्तरों पर, अब किसानों के लिए चिंता का विषय नहीं है।औद्योगीकरण ने बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान किए हैं और ग्रामीण आबादी के लिए आय के स्रोत के रूप में द्वितीयक क्षेत्र को खोल दिया है।इससे उनकी आय बढ़ाने में संभावित आजीविका और सहायता प्राप्त परिवारों की सीमा में वृद्धि हुई है।हालांकि अधिक व्यक्तियों ने शहरों में प्रवास करना शुरू कर दिया है, लेकिन यह उन आर्थिक विकास से ऑफसेट हो सकता है जो ये मजदूर उत्पादों और सेवाओं के निर्माण में काम करके राष्ट्र में लाते हैं।जाति व्यवस्था के उन्मूलन से समाज और उसकी सोच को लाभ हुआ है। इसने समुदाय को अस्पृश्यता जैसे मुद्दों पर काबू पाने में सहायता की है।समाज इस सुधार के परिणामस्वरूप विकसित हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप विकास की दर में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
नौकरी अब किसी व्यक्ति की जाति, पंथ या धर्म के आधार पर आवंटित नहीं की जाती है।आज के गांव में सामाजिक प्रतिष्ठा से ज्यादा प्रतिभा का महत्व है।उच्च जाति का प्रभुत्व समाप्त हो गया है, जिससे समाज योग्यता-आधारित प्रतिस्पर्धा के स्तर पर आ गया है।यहां तक कि समाज के कमजोर हिस्से भी फल-फूलेंगे, जो लंबे समय में देश की आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को कम करेगा। सरकारी जागरूकता कार्यक्रमों और बाहरी दुनिया के संपर्क के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने परिवार के आकार को सीमित करने के महत्व के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं। गरीबी के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक अधिक जनसंख्या थी। लोग एक मामूली परिवार होने के मूल्य के बारे में अधिक जागरूक हो रहे हैं और खतरनाक गति से परिवार के आकार को बढ़ाने के बजाय अपने बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बदलते परिप्रेक्ष्य की सहायता से , सदियों पुरानी पारिवारिक प्रथाएं और परंपराएं मुक्त हो रही हैं।बढ़ी हुई ग्राम संरचना की टैगलाइन "छोटा और खुशहाल परिवार" बन गई है।

चुनौतियों

हालांकि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सुधार के लिए काफी प्रयास किए गए हैं , लेकिन हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।समुदायों में दीर्घकालिक परिवर्तन लाने में प्रशासन के पास कई बाधाएं हैं।इसका प्राथमिक कारण अधिक जनसंख्या है , जो अधिक बेरोजगारी और गरीबी की ओर ले जाता है।गांवों में रहने वाले लोगों को शिक्षित करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं , लेकिन उचित क्रियान्वयन और सूचना का प्रसार चिंता का विषय बना हुआ है।एक अन्य मुद्दा ग्राम समुदायों में गहरी अंतर्निहित जाति व्यवस्था है , जिसका ग्रामीण भारत में रहने वाले व्यक्तियों की सोच और दृष्टिकोण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।प्रत्येक जाति और समुदाय के व्यक्तियों के स्थापित कर्तव्यों ने सामाजिक विकास को बाधित किया है।सदियों पुराने रीति-रिवाज़ और शासन अनिवार्य स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सरकारी पहलों में बाधक बने हुए हैं।ग्रामीण क्षेत्र के लिए नेताओं के निर्माण के लिए राजनीतिक समर्थन का गांवों के सच्चे हितों पर प्रभाव पड़ता है।जो लोग राजनीतिक नेताओं का अनुसरण करते हैं उन्हें पदोन्नत किया जाता है और ग्राम समुदायों में नेतृत्व के पदों पर पदोन्नत किया जाता है।हालाँकि , गाँवों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख चयन मानदंड को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए , और इसे राजनीतिक दलों के पक्ष में वापस करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।गाँव के परिवर्तन पर शक्ति संरचना का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, और यदि यह खतरे में पड़ जाता है, तो गाँव के

समुदायों का विकास और उन्नति खतरे में पड़ जाएगी।इसके अलावा , किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रति सुस्ती , जो ज्यादातर पितृसत्ता के अहंकार से प्रेरित होती है , ग्रामीण भारत के प्रगतिशील विकास में एक बड़ी बाधा है।गांवों में , घर के सबसे बड़े पुरुष के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है।और समाज की उन्नति के लिए किसी भी संशोधन या सुधार को समय-सम्मानित प्रथाओं का उल्लंघन माना जाता है।परिवार के मुखिया का उद्देश्य परिवार की सदियों पुरानी परंपराओं की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना है , और इसमें किसी भी बदलाव को स्वीकार नहीं किया जाता है।यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से किसी भी परिवर्तन के कार्यान्वयन में बाधा प्रदान करता है।

एक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक परिवर्तन

अकादमिक शब्दजाल में , "परिवर्तन" वाक्यांश को एक प्राकृतिक घटना माना जाता है।यह सुझाव देता है कि जिस चीज पर इसे लागू किया जाता है वह स्थिर होने के बजाय पूरे समय बदलती रहती है।इस दृष्टिकोण के अनुसार , सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है कानून , सिद्धांत, दिशा और निरंतरता का अभाव।जब भी हम एक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो हम निरंतरता की अवधारणा का परिचय दे रहे होते हैं।एक प्रक्रिया को एक निरंतर परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि शुरू से ही एक स्थिति में मौजूद कारकों की गतिविधि के परिणामस्वरूप परिभाषित तरीके से होता है।संचार , समाजीकरण, आवास, एकीकरण, विघटन, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो मौजूद हैं।जब हम किसी प्रक्रिया की जांच करते हैं , तो हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण के अनुक्रम की तलाश करते हैं।यह संभव है कि प्रक्रिया के दो चरणों की गुणवत्ता भिन्न होगी।न तो वही रास्ता लिया जाता है और न ही एक ही दिशा।

एक प्रक्रिया आगे या पीछे हो सकती है , आगे या पीछे जा सकती है , या प्रगति या प्रतिगमन की स्थिति में हो सकती है।नतीजतन, एक प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा में एक चरण से दूसरे चरण में प्रगति के रूप में परिभाषित किया जाता है।प्रोसेसिंग सिस्टम पर इसके प्रभाव में सिस्टम-सस्टेनिंग और सिस्टम-ट्रांसफॉर्मिंग दोनों है।सामाजिक परिवर्तन की कुछ प्रक्रियाएँ एक विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था का पुनर्जनन ला सकती हैं , जबकि अन्य प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप उस सामाजिक व्यवस्था में शिथिलता और पतन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।समाजशास्त्रीय प्रक्रियाएं सामाजिक संरचना का एक घटक हैं , और हम नियमित रूप से सामाजिक प्रणालियों को बनाए रखने या संशोधित करने के उद्देश्य से गतिविधियों में उनका सामना करते हैं।

निष्कर्ष

भारत विविध जलवायु परिस्थितियों और विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के साथ एक विविध राष्ट्र होने के नाते , यह भारत के पारिस्थितिक मानचित्र का निर्माण करके एक अच्छी शुरुआत होगी।इसका उद्देश्य उन स्थानों पर जोर देना होगा जो उनके अस्तित्व में कठिनाई का सामना कर रहे हैं और प्रत्येक स्थान के लिए एक अलग दृष्टिकोण तैयार करना जिस मुद्दे का वे सामना कर रहे हैं।यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में अधिक सहायता प्रदान करेगा और भारतीय गांवों को एक ठोस संरचना प्रदान करेगा।इसके अलावा , समाज के जाति आधारित स्तरीकरण को प्रोत्साहित करने वाले वर्तमान रवैये का मुकाबला करने के लिए जागरूकता गतिविधियों और अभियानों को विकसित किया जा सकता है।समुदाय के कल्याण के लिए काम करने वालों के हाथों में सत्ता का विविधीकरण होना चाहिए।ग्रामीण गांवों की शक्ति संरचना को बढ़ाने के लिए राजनीति को सरल बनाया जा सकता है।कुल मिलाकर, हमारी आजादी के बाद से भारतीय गांवों की संरचना में काफी बदलाव आया है।हालांकि , इसके आगे के विकास के लिए बहुत कुछ किया जाना है।गाँव हमारे देश का एक आंतरिक तत्व हैं और राष्ट्र के विकास के लिए उनके बदलते रूप का अत्यधिक महत्व है।

संदर्भ

1. धनगारे, डी.एन. (2007)। इतिहास के माध्यम से समाजशास्त्र का अभ्यास करना। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 42 (33-34), 3414-3421, 3502-3508।
2. धनगारे, डी.एन. (2011)। विरासत और कठोरता: बॉम्बे स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी और महाराष्ट्र में विश्वविद्यालयों में इसका प्रभाव। पटेल में, एस. (सं.), डूइंग सोशियोलॉजी इन इंडिया: वंशावली, स्थान, और प्रथाएं (पीपी. 127–157)। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. ड्यूमॉन्ट, एल। (1957)। भारत के समाजशास्त्र के लिए: ग्राम अध्ययन , रिश्तेदारी। भारतीय समाजशास्त्र में योगदान, 1, 7-64।
4. गुप्ता, डी. (2005)। विदर द इंडियन विलेज: कल्चर एंड एग्रीकल्चर इन रूरल इंडिया। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 40(8), 751-758।
5. गुप्ता, एन। (2007)। सामाजिक ज्ञान का सार्वभौमीकरण और स्वदेशीकरण: पश्चिमी आधिपत्य को तोड़ना। समाजशास्त्रीय बुलेटिन, 56(3), 426-430।
6. शर्मा, के एल (2007)। जाति, वर्ग और वैश्वीकरण: निरंतरता और परिवर्तन। चौधरी, के. (सं.), वैश्वीकरण, शासन सुधार और भारत में विकास (पीपी। 241-258) में। नई दिल्ली: सेज प्रकाशन।
7. सिंह, वाई. (1967)। भारत में समाजशास्त्र का दायरा और पद्धति और भारत के लिए समाजशास्त्र: उभरता परिप्रेक्ष्य। उन्नीथन में , टी.के.एन., सिंह, योगेंद्र, सिंघी, नरेंद्र, देवा, इंद्र (संस्करण), भारत के लिए समाजशास्त्र (पीपी। 19-37)। दिल्ली: अप्रेंटिस हॉल